वाद दायर करने, जमानत प्राप्त करने और सुनवाई का अवसर मिलता है, फैसले का अवसर मिलता है, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। मेरठ में ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित भी हो गया है, उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश abeyance रखा गया। मैं इस विषय पर अपनी बात रखते हुए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि kept in abeyance का आदेश स्थगित हो और ई-फाइलिंग सेंटर की व्यवस्था को चालू किया जाए, धन्यवाद।

Demand to Include Agricultural Sciences in the Syllabi of Navodaya and Kendriya Vidyalayas

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, नर्मदे हर! मैं आज सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और उनका व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस देश के अंदर कृषि प्रधान देश होने के कारण महाविद्यालयों में और स्कूलों में कृषि विषयों को भी पढ़ाने का काम होना चाहिए।

महोदय, देश के अंदर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हजारों विद्यालय संचालित हैं और साथ ही राज्य सरकार के विद्यालय भी हजारों की संख्या में संचालित हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और शिक्षक रहा हूं। मुझे लंबे समय तक इस बात का एहसास हुआ है कि जिन कॉलेज और स्कूल्स में कृषि विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, वह अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मैं सीबीएसई में और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए मांग करता हूं, ताकि हमारे किसान के बेटा-बेटी कृषि विषय को पढ़ पाएं और जब वे घर की ओर लौटें, तो बहुत अच्छे तरीके से, उच्च तकनीकी तरीके से खेती-बाड़ी का काम कर सकें और गांव के भाइयों और बहनों को तकनीकी रूप से खेती करने के लिए मदद कर पाएं। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को और साथ ही हमारे कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब के नेतृत्व में देश का किसान निरंतर तरक्की कर रहा है और खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश के नवोदय विद्यालयों में और केन्द्रीय विद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कृषि विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की मांग करता हूं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं,नर्मदे हर!

Demand for adequate means of transport for the city of Jabalpur, Madhya Pradesh

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, मैं जबलपुर, देश के केन्द्र में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है, जहां से देश के विभिन्न भागों तथा आसानी से प्रभावी परिवहन संभव है।

यह शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रमुख केन्द्र है। देश के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं, जिससे इसको logistics और व्यापार के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। भारत सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गतिशील योजना, भारत माला परियोजना और dedicated freight corridor जैसी पहलों के तहत देश में logistics infrastructure को आधुनिक और कुशल बनाया जा सकता है। जबलपुर का नवीनीकृत और उच्च क्षमता वाला हवाई अड्डा ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Zero Hour is over. Now, Question Hour ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, हमारा नोटिस नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हमारे लोगों ने नोटिस दिया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not allowed. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Now, Question Hour.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'NAMAMI GODAVARI' RIVER INITIATIVE

*1. DR. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) actions taken by Government in collaboration with State Government to assess the irrigation needs in the Marathwada region of Maharashtra, which is experiencing water shortages that hinder agricultural growth;
(b) whether Government has received representation for the 'Namami Godavari' river cleaning initiative similar to 'Namami Gange', the measures initiated thereon; and
(c) whether the Central Government, in conjunction with the State Government is planning to dispatch a team of experts to Marathwada to formulate a strategy for tackling the water scarcity problem, if not, the reasons therefor, if so, the steps which will be taken thereon?